भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1484
जिसका उत्तर बुधवार 15 मार्च, 2017 को दिया जाना है

पूंजीगत माल क्षेत्र को वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की योजना

1484. श्री पि. भट्टाचार्य:
श्रीमती रजनी पाटिल:
श्री दर्शन सिंह यादव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र को वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की योजना आरंभ की है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस योजना के तहत कितनी अनुदान राशि वितरित की गई है;
(ग) क्या सरकार ने पूंजीगत माल के उत्पादन तथा नियोजन एवं विनिर्माण क्षेत्र के विकास में बढ़ोतरी करने के लिए कोई लक्ष्य तय किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, हां।

(ख): अब तक, इस स्कीम के विभिन्न संघटकों के तहत ₹49.98 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

(ग) और (घ): सरकार ने राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति प्रकाशित की है। इस नीति में उत्पादन को बढ़ाकर लगभग ₹7,50,000 करोड़ तक करने, प्रत्यक्ष रोजगार को वर्ष 2025 तक 5 मिलियन तक करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति में केपिटल गुड्स के भाग को वर्तमान 12% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 20% करने की भी परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति का विस्तृत विवरण भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

केपिटल गुड्स स्कीम के तहत, अब तक 14 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इनमें से, 4 प्रस्ताव प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे सेंट्रल मेन्युफैक्चरिंग टेक्नॉलोजी इंस्टिट्यूट (सीएमटीआई), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास, पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नॉलोजी, कोयंबटूर, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर (सी' टार्क), कोयंबटूर द्वारा प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्रों से संबंधित हैं। साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र हेतु 4 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है, जिनमें बेंगलुरु स्थित एचएमटी मशीन टूल्स तथा एचईसी लिमिटेड, रांची में दो प्रशिक्षण केन्द्र तथा चाकन, महाराष्ट्र एवं बारदोली, गुजरात में दो साझा इंजीनियरी संस्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, तुमकुर में एकीकृत मशीन टूल पार्क की स्थापना का एक प्रस्ताव भी अनुमोदित किया जा चुका है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस स्कीम के प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम के तहत 5 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतर आविष्कार योजना तथा इंपेक्टिंग रिसर्च इन्नोवेशन एंड टेक्नॉलोजी (इम्प्रिंट) स्कीम के तहत केपिटल गुड्स उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को भी भारी उद्योग विभाग द्वारा आंशिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है।

*****